

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1898 / 2012 / बांसवाडा

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन-बांसवाडा

अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स ए.वी.एस.एल.फोर्ड्स प्रा.लि.
हलोल, गुजरात

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

विभाग की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 28.09.2016

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-बांसवाडा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 94/आरवैट/2011-12/उपा/अपील्स/अलवर के आदेश दिनांक 03.02.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 1,92,546/-को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.07.2011 को पडूना, उदयपुर में वाहन चेकिंग के दौरान वाहन संख्या आर.जे.-06/जीए-5922 को चेक करने पर उसमें परिवहनित माल पी वी सी फिलर हलोल (गुजरात) से भिवाडी (राजस्थान) के परिवहनित किया जा रहा था, जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :-

1. न्यू महावीर, कारेलीबाग बडौदा(गुजरात)की बिल्टी/जी.आर.नं.2469 दिनांक 10.07.2011
2. मै.एवीएसएल फोर्ड्स प्रा.लि., हलोल(गुजरात) की बिल बुक नम्बर-01 का इनवाइस नं. 10 दिनांक 10.07.2011 कीमत रु. 1,78,138/- जो मैसर्स श्रीराम केबल्स प्रा.लि., चौपानकी, भिवाडी को जारी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया कि परिवहनित माल के साथ विधिक घोषणा पत्र वैट-47 नहीं है, जो अधिनियम की धारा 76 (2) सपठत नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 9470264 दो प्रति में प्रस्तुत किया गया है, जिसको पश्चावर्ती सोच मानते हुए अमान्य कर अधिनियमकी धारा 67 (6) के अन्तर्गत शास्ति

रु. 1,92,546 /-आरोपित की। उक्त आरोपित शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2012 से असन्तुष्ट होकर यह अपील कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिकथन किया कि अपीलीय अधिकारी का निर्णय नियम व विधि के विरुद्ध है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के साथ वैट-47 नहीं था इस कारण कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित की थी, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि नोटिस के जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत करना पश्चातवर्ती सोच है, जिसे स्वीकार किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के विरुद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

नोटिस तामील होने के पश्चात भी अप्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर गुणावगणु के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा रहा है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गयी है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.3012 को पारित कर अपास्त किया गया है।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 9470264 नोटिस के जवाब के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 13 पर दो प्रतियों में उपलब्ध है, जिसका उल्लेख अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में किया है। अतः घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति व कर आरोपित करना उचित नहीं है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ



घोषणा वैट-47 प्रस्तुत कर दिया गया थो तथा घोषण पत्र वैट-47 वक्त चेकिंग प्रस्तुत नहीं करने के कारणों को उजागर किया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स डी पी मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उस सन्दर्भ में उद्धृत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट-2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट-2 पेज 37 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

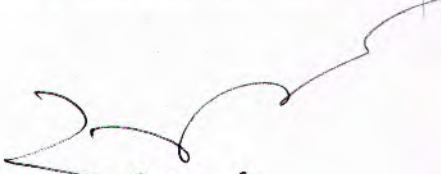


".....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में नोटिस की पालना घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे अस्वीकार कर शास्ति आरोपित करना उचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2013 में समावेश करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिसकी पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य